

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के० सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2482-एक/2014 - विरुद्ध आदेश दिनांक
11-10-2012 - पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण

क्रमांक 133/2010-11 निगरानी

1- रूप सिंह 2- अभिलाख सिंह 3- सुरेन्द्रसिंह

तीनों पुत्रगण रामनारायण सिंह ग्राम बुधारा

तहसील पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

राजकुमार सिंह पुत्र घमण्डी सिंह

ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना

---अनावेदक

(आवेदक की ओर से श्री ए०के०बाजपेयी अभिभाषक)
(अनावेदक की ओर से श्री एस०के०अवस्थी)

आ दे श

(आज दिनांक 18 - 11 - 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक
133/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-10-12 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू
राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारंश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार पोरसा के समक्ष
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ग्राम बुधारा स्थित आराजी क्रमांक 244 रकबा 0.439 हैक्टर पर
कब्जा दर्ज करने का आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया कि संबत 2030 में रु.
5000/-प्रीमियम लेकर 50 वर्ष के लिये नाथू सिंह, बच्चूसिंह ने भूमि जुताई थी तभी से
वह काविज होकर खेती कर रहा है। अतएव उसका कब्जा दर्ज किया जावे। उक्त पर



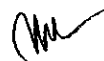


तहसीलदार पोरसा ने प्रकरण क्रमांक 11/93-94 अ 6 अ पंजीबद्ध किया एवं सुनवाई करके दिनांक 29-1-1996 को आदेश पारित किया कि यदि आवेदकगण का भूमि पर कब्जा सिद्ध होता है तब पटवारी कब्जा दर्ज करे। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी अम्वाह के समक्ष अपील क्रमांक 72/2005-06 प्रस्तुत हुई। गजूसिंह की मृत्यु होने पर वारिसान को रिकार्ड पर लेने हेतु व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4 के तहत आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रस्तुत किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-08 पारित किया तथा मृतक के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की। इस आदेश के विरुद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 175/07-08 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10-6-11 से निगरानी निरस्त की गई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 133/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-10-12 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि गजूसिंह को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रतिअपीलार्थी क्रमांक 4 बनाया गया था जबकि गजूसिंह की मृत्यु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के पूर्व हो चुकी थी, जिसके कारण व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं एवं मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता। अनावेदक के अभिभाषक का तर्क है कि गजूसिंह कब मरा, इसकी जानकारी अनावेदक को नहीं थी और जैसे ही जानकारी हुई, उसके द्वारा व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। गजूसिंह के अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अन्य पक्षकार भी हैं जिसके कारण अपील अवैटमेंट में समाप्त नहीं की जा सकती।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के






समक्ष तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 29-1-96 के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करते हुये गजू सिंह को अनावेदक बनाया है और जब उसे गजू सिंह की मृत्यु होने की जानकारी हुई , जानकारी होते हुये उसने व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत कर मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने की प्रार्थना की है। वैसे भी सामान्य सिद्धांत है कि जब मामले में मृतक पक्षकार के अतिरिक्त अन्य पक्षकार भी हों, तब संपूर्ण मामला अवेट नहीं होता है , जबकि विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के आवेदन में स्पष्ट बताया गया है कि मृतक गजू सिंह एवं उसके वारिसान भिण्ड जिले के निवासी होने से एवं अपीलांत ग्राम बुधारा तहसील पोरसा जिला मुरैना का रहने वाला होने से मृतक की जानकारी में समय लगा है। अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह कैंप पोरसा के प्रकरण में गजूसिंह के अलावा अन्य 4 रिस्पाण्डेन्टस भी हैं जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक 12-8-08 से मृतक के वारिसान को रिकार्ड पर लेने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12-8-08, अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 175/2007-08 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-6-11 तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11-10-12 में निकाले गये निष्कर्ष सामान्यतः समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एवं तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 133/10-11 निगरानी में पारित आदेश दि0 11-10-12 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

R
2/5


(एम0के0सिंह)

सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर